

-1-

C. 58/151

न्यायालय माननीय बोर्डे आफ रेवेन्यू म०१० ग्वालिबर  
 पुस्तक क्रमांक / नि०मात

R 373-II/2005  
 श्री. ... द्वारा आज दि० 28/3/05 को प्रस्तुत।  
 भवन सचिव  
 राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालिबर  
 28 MAR 2005

- 1:- राजकुमारीसिंह उम्र 90 साल पुत्र मोरसिंह
- 2:- जीभलाखीसिंह जाय 62 साल पुत्र राजकुमारीसिंह
- 3:- देवराजीसिंह जाय 50 साल पुत्र राजकुमारसिंह
- 4:- शुद्धीसिंह उर्फ रामवलीसिंह उम्र 55 सालपुत्र राजकुमारीसिंह
- 5:- कन्यामसिंह उम्र 73 साल पुत्र फरीसिंह
- 6:- सुवासिंह उम्र 45 साल पुत्र कन्यामसिंह
- 7:- मानीसिंह उम्र 48 साल पुत्र कन्यामसिंह
- 8:- मुरारीसिंह फौज वारिस
- 1- प्रमोदीसिंह उम्र 35 साल पुत्र मुरारीसिंह साकिन मुन्हाडा मकरा धार कर कापुरा परगना व जिल्लासिंह

-- आवेदकगण

बनाम

- 1:- कुआरबहादुरसिंह उम्र 65 सालपुत्र गनपतसिंह
- 2:- राजेन्दीसिंह फौज वारिस -
  - 1-र जयेन्दीसिंह उम्र 50साल
  - 2-कुशमपतिसिंह उम्र 49 साल
  - 3-रामकृष्णसिंह उम्र 38 साल
  - 4-रामगोविन्दीसिंह उम्र 32 साल
 पुत्रगण राजेन्दीसिंह फौज वारिस

28/3/05  
 28/3/05

R  
 12

28/3

निवासीग्राम नुन्हाटा मजरा चार कर का  
पूरा तहसील व जिला भिण्डमण्ड

--अनावेदकगण

प्रपत्र 301/94-95 अमल न्यायालय की मजरा महोदय  
श्री एसकेवाण्डेय साहब बाबल संभाग मुरैना केम  
भिण्ड द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक  
23-12-2004 के विरुद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

प्रकरण के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:-

1. विनय पार्थीक ग्राम नुन्हाटा तहसील भिण्ड का आराजी क्रमांक  
904 जो बंदोबस्त के पूर्व का है इसका कूल रकबा करीब 35 बीघा  
12 विस्वा है इसके चार बेट तत्कालीन रेवेन्यू अधिकारियों के द्वारा  
किये गये हैं जो क्रमा: इस प्रकार है कि-

1. 904/1 रकबा 7 बीघा 5 विस्वा 10 विस्वांसी

2. 904/2

3. 904/3

4. 904/4 रकबा 1.097

तत्कालीन कागजात पटवारी में गोडा निस्तार की भूमि अंकित  
है।

2. यहाँक, आराजी नं० 904/1 रकबा 7 बीघा 5 विस्वा 10 विस्वांसी  
में से रकबा 1 बीघा 12 विस्वा 10 विस्वांसी का बयनामा भूरीसंह

*[Handwritten Signature]*

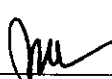
*[Handwritten Initials]*

XXXIX(a)BR(H)-11


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 373-एक/05

जिला - भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-11-16	<p>यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 301/94-95/अपील में पारित आदेश दिनांक 23-12-2004 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।</p> <p>2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकों द्वारा तहसील न्यायालय में इस आशय की शिकायत पेश की गई कि ग्राम नुन्हटा स्थित विवादित भूमि सर्वे नं. 904/4 रकबा 1.097 आरे कागजात पटवारी में मुताबिक गोंडा/निस्तार दर्ज है जिस पर आवेदकगण अतिक्रमण कर फसल कर रहे हैं । उक्त शिकायत पर से विचारण न्यायालय ने प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच की कार्यवाही प्रारंभ की एवं आदेश दिनांक 23-2-93 द्वारा प्रकरण खारिज किया। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदकों ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने निरस्त की । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अनावेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जिसमें अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित किया है । अपर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।</p> <p>3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उद्धरित किये गये हैं ।</p> <p style="text-align: right;"></p>	



स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>K/1a</p>	<p>4/ अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय हैं । 5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि यह प्रकरण शासकीय भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने तथा आवेदकों ने प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय भूमि होना व्यक्त किया है । व्यवहार न्यायालय द्वारा भी विवादित भूमि को ओपन मान्य किया है तथा प्रकरण में प्रस्तुत पटवारी एवं गिरदावल रिपोर्ट के अनुसार भी प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर आवेदकों का अतिक्रमण सिद्ध है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में विद्वान अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित करने में कि वे अतिक्रमकों को विवादित शासकीय भूमि से बेदखल कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश देने में कोई न्यायिक एवं विधिक त्रुटि नहीं की गई है । विद्वान अपर आयुक्त का आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश स्थिर रखा जाता है । पक्षकार सूचित हों । अभिलेख वापिस हो ।</p>	<p> सदस्य</p>